



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १२८]
No. 128]

नई दिल्ली सोमवार, मार्च 31, 1980/चैत्र 11, 1902
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 1980/CHAITRA 11, 1902

इस भाग में रैमन पृष्ठ संख्या वी जारी है जिससे कि पह अलग संकाशन के रूप में
रक्ता या अन्य

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(ओद्योगिक विकास विभाग)

आदेश
नई दिल्ली, 31 मार्च, 1980

फा०धा० 232(अ)/18FB/आई०डी०धा००८०/—भारत सरकार
के उद्योग मंत्रालय (ओद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० फा०धा०
192(प्र)/18-चैत्र/आई वी आर ए/79; तारीख 31 मार्च, 1979 (जिसे
हमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने
उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की
धारा 18 चैत्र की उपधारा (1) के अन्त (अ) द्वारा प्रदत्त शर्तियों का
प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख
से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पति के हस्तान्तरण पक्षों, करारों,
व्यवस्थापनों, पंचाईं, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (उनसे भिन्न
जो बैंकों और केन्द्रीय संस्थाओं के प्रतिशूल वायिलों से संबंधित हैं), जिसका
मैसर्स महादेव टेस्टाइल मिल, हुबली, कर्नाटक नामक ओद्योगिक एक पक्षकार
है या जो ऐसे ओद्योगिक उपकरण को लागू हो सकती है, प्रवर्तन
ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त
तारीख से पूर्व तद्दीन प्रोब्रूफ या उद्घृत होने वाली सभी
बाध्यताएं और वायिल उक्त अवधि तक निलम्बित रहेंगे;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की
अस्तित्वावधि एक वर्ष तक और बढ़ा वी जानी चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,
1951 (1951 का 65) की धारा 18 चैत्र की उपधारा (2) के साथ
पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश
की अस्तित्वावधि 30 मार्च, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित
है, और बढ़ाती है।

[फा० सं० 3/2/79 सी०य०सी]

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
ORDER

New Delhi, the 31st March, 1980

S.O. 232(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the
Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 192(E)/18FB/
IDRA/79, dated the 31st March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise
of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of
section 18FB of the Industries (Development and Regulation)
Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all
contracts, assurances of property, agreements, settlements,
awards, standing orders or other instruments in force immediately
before the date of issue of the said Order (other than

those relating to secured liabilities to bank and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Mahadeva Textile Mills, Hubli, Karnataka, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 30th March, 1981.

[File No. 3(2)/79 Cus.]

कांग्रेस 233(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क द्वारा प्रवत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (ओद्योगिक विभाग) के आदेश सं० कांग्रेस 325 (अ) तारीख 18 मई, 1978 में विमुलित करती है, अधिर्थतः—

उक्त आदेश में “मवत्त्व (अंशकालिक)”, शीर्ष के निम्ने प्राप्ति 5ब का लोप किया जाएगा।

[कांग्रेस 4(1)/77-सी०य०एम०]

S.O. 233(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 325(E) dated the 18th May, 1978, namely:—

In the said Order, under the heading 'Members (Part-time)', entry 5B shall be omitted.

[F. No. 4(1)/77-Cus.]

कांग्रेस 234(अ)/18 अ/प्राई श्री पार ए/80—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (ओद्योगिक विभाग) के आदेश सं० कांग्रेस 618 (अ)/18क/प्राई श्री पार ए/79, तारीख 31 मार्चबूर, 1979 द्वारा सखिव, बंद और रुण उद्योग विभाग परिचमी बंगल सरकार, कलकत्ता को सम्पूर्ण ओद्योगिक उपकरण अधिकारी श्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध उसमें विनिरिष्ट अधिकारी के निए अहंग करते के लिए प्राप्तिकृत किया है।

अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रवत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपायक अनुसूची में ऐसे व्यापारों, निवेशनों और परिसीमाओं को विनिरिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए कम्पनी प्रधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त ओद्योगिक उपकरण को उसी शीर्ष में लागू होता रहेगा जैसी वह पूर्णत अधिनियम की धारा 18क के अधीन आदेश जारी किए जाने के पूर्व उसे लागू था।

अनुसूची

कम्पनी प्रधिनियम, 1956
के उपबन्ध

ऐसे व्यापार, निवेशन, परिसीमाएं
जिनके अधीन रहते हुए स्थान (1)
में वर्णित उपबन्ध उपकरण को लागू होंगे।

1

धारा 166 और 210(1)

इन धाराओं के उपबन्ध उक्त ओद्योगिक उपकरण को इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि यद्यपि कम्पनी का तुलन पत्र और लाभ तथा हार्नि का लेखा वापिक साधारण प्रधिवेशन के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है।

1

धारा 217

धारा 224 और 225

धारा 293(1)(अ)

धारा 169 और 294

2

किंतु भी उक्त उपकरण तुलन पत्र और लाभ तथा हार्नि का लेखा सामान्य रूप में तैयार करेगा और उन्हें कानूनी विवरणियों के साथ कम्पनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा।

इस धारा के उपबन्ध उक्त ओद्योगिक उपकरण को उस सीमा तक तागू नहीं होंगे जिस सीमा तक कि बोर्ड की रिपोर्ट वापिक साधारण प्रधिवेशन के समक्ष रखे जाने के लिए अपेक्षित न हों।

इन धाराओं के उपबन्ध उक्त ओद्योगिक उपकरण को इस शर्त के प्रधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे कि लेखापरीक फेन्ड्रीय सरकार धारा नियुक्त किए जाएंगे।

इस उपधारा के उपबन्ध उक्त ओद्योगिक उपकरण को उन शर्तों के अधीन रहते हुए लागू नहीं होंगे, जिन्हें सरकार समय-समय पर अधिरोपित करे।

इन धाराओं के उपबन्ध उक्त ओद्योगिक उपकरण को लागू नहीं होंगे।

[कांग्रेस 2(15)/79-सी०य०एम०]

श्री० राय, संयुक्त सचिव

S.O. 234(E)/18E/IDRA/80.—Whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 618 (E)/18AA/IDRA/79, dated the 31st October, 1979, the Central Government has authorised Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, Calcutta, to take over the management of the whole of the industrial undertaking viz., Sree Saraswati Press Limited, Calcutta, for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby specifies, in the Schedule annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the order under section 18AA of the aforesaid Act.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions, limitations subject which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking.
--	---

1

Sections 166 and 210(1) Provisions of these sections shall not apply to the said industrial undertaking, subject to the condition that while the balance sheet and profit and loss account of the Company need not be placed before the annual general meeting, it shall, however, prepare Balance Sheet and Profit and Loss Account as usual and file them with the Registrar of Companies along with Statutory returns.

2

1	2	1	2
Section 217	Provisions of this section shall not apply to the said industrial undertaking to the extent that the Board's report is not required to be placed before the general meeting.	Section 293(1)(d)	Provisions of this sub-section shall not apply to the said industrial undertaking subject to such conditions that Government may impose from time to time.
Sections 224 and 225	Provisions of these sections shall not apply to the said industrial undertaking subject to the condition that auditors shall be appointed by the Central Government.	Sections 169 and 294	Provisions of these sections shall not apply to the said industrial undertaking.

[F. No. 2(15)/79-C US.]
B. ROY, Lt. Secy,

